

उत्तर प्रदेश सरकार ने नजी कंपनियों को ई-मोबिलिटी में नविश के लिये आमंत्रित किया चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नजी कंपनियों को अपने ई-मोबिलिटी पुश में नविश करने के लिये आमंत्रित किया है। राज्य ने अगले पाँच वर्षों में 75 ज़िलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य बंदि:

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परविहन नगिम (UPSRTC) ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिये बोलियाँ आमंत्रित करते हुए एक नविदिा जारी की है।
- पहले चरण में अगले वत्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही 5,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
 - ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के अलावा, बोलीदाता संबद्ध वदियुत तथा नागरकि बुनयादी ढाँचे का भी ध्यान रखेगा।
 - उन्हें राजस्व साझाकरण मॉडल पर मौजूदा अंतर-ज़िला मार्गों पर परचालन की अनुमति दी जाएगी।
- ई-बसों की तैनाती से राज्य के सार्वजनिक गतशीलता बेड़े से कार्बन उत्सर्जति करने वाली 12,000 डीज़ल बसें चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परविहन नगिम (UPSRTC)

- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परविहन नगिम है जो उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर भारत के आस-पास के राज्यों को सेवा प्रदान करता है।
- यह राज्य और अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के रूप में संचालित होती है तथा उत्तर भारत में बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
- नगिम का कॉर्पोरेट कार्यालय **लखनऊ में स्थित है।**
- सड़क परविहन अधनियिम, 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 को यूपी सरकारी रोडवेज़ का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परविहन नगिम (UPSRTC) कर दया गया। इस उपक्रम के उद्देश्य थे:
 - इससे संबंधित सड़क परविहन क्षेत्र का विकास व्यापार और उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।
 - परविहन के अन्य साधनों के साथ सड़क परविहन सेवाओं का समन्वय।
 - राज्य के नवासियों को पर्याप्त, कफायती और कुशलतापूर्वक समन्वित सड़क परविहन सेवा प्रदान करना।